वार्षिक बज़ट 2014–15 में नई समाज कल्याण योजनाएं

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये अपना पहला बज़ट प्रस्तुत किया है। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिये कुछ नई सामाजिक विकास योजनाएं घोषित की गई हैं.

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
वित्त मंत्री ने बजट में इस कार्यक्रम की घोषणा मानसून पर निर्भर सिंचाई के जोख़िम को कम करने के उपाय के तौर पर की है. योजना का उद्देश्य किसानों को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराना है. वित्त मंत्री ने इस उद्देश्य के लिये रू 1000 करोड़ की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव किया.

2. स्वस्थ भारत अभियान
इस कार्यक्रम का नारा है– ''2019 तक पूर्ण स्वच्छता''. स्वच्छता के महत्व को महसूस करते हुए वित्त मंत्री ने इस लक्ष्य को हासिल करने में सभी नागरिकों से सहयोग मांगा है. वर्ष 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष भी है.

3. हर किसान के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
सरकार ने यह योजना मिट्टी की बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र शुरू की है जिससे खेती के संसाधनों का उपयुक्त इष्टतम उपयोग हो सके. सरकार एक मिशन के तौर पर हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करायेगी. इसके लिये 100 करोड़ रू आबंटित किये गये हैं. देशभर में 100 चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये रू 56 करोड़ की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है.

4. किसानों के लिये समर्पित टीवी चैनल
कृषि और संबद्ध क्षेत्र के हितों के प्रति समर्पित ''किसान टीवी'' चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जायेगा. यह किसानों में नई खेती तकनीकों, जल संरक्षण, आर्गेनिक और फार्मिंग आदि के संबंध में नवीनतम सूचनाओं का विस्तार करेगा.

5. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के विस्तार और उप–पारेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिये फीडर पृथक्कीकरण हेतु ''दीपदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' शुरू की जायेगी. इसका दीर्घावधि उद्देश्य सभी घरों को 24×7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाना है. इस योजना के लिये रू 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

6. वन बंधु कल्याण योजना
जनजातीय लोगों के कल्याण के लिये रू 100 करोड के शुरूआती आबंटन के साथ ''वन बंधु कल्याण योजना'' शुरू की जा रही है.

7. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
सरकार ने रू 100 करोड़ की शुरूआती निधि के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नामक एक नई योजना शुरू की है, जिससे जागरूकता पैदा करने और महिलाओं की कल्याण सेवाओं की दक्षता के सुधार में मदद मिलेगी. सरकार इस देश के लोगों को कन्याओं और महिलाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के अभियानों पर फ़ोकस करेगी. संवेदीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होनी चाहिए और इस प्रकार स्कूल पाठयक्रम में महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल किये जाने के संबंध में एक अलग अध्याय होना चाहिये.

8. राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं विस्तार योजना
धरोहर शहर विकास एवं विस्तार योजना (एचआरआईडीएवाई) नामक कार्यक्रम इन शहरों की विशिष्ट धरोहरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिये शुरू की जानी हैं. शुरूआत में यह कार्यक्रम मथुरा, अमृतसर, गया, कांचिपुरम, वेल्लानकानी तथा अजमेर में शुरू किया जा रहा है. इस उद्देश्य के लिये रू 200 करोड़ निर्धारित किये गये हैं. परियोजना के तहत सरकार अकादमिक संस्थानों और स्थानीय समुदाय के जरिये किफायती प्रौद्योगिकियों के संयोजन के साथ काम करेगी.

9. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना आधारित समन्वित परियोजना संचालित करने के लिये की जायेगी. योजना में आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है. सुपुर्दगी की वरीयतन पद्धति विभिन्न योजना निधियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीज) के जरिये होगी. यह गुजरात के उदाहरण पर आधारित है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के *शहरी विकास मॉडल* को सफलतापूर्वक पेश किया है**,** जिसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग दक्ष नागरिक अवसंरचना और संबद्ध सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं.

10. अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु परंपरागत कलाओं और दस्तकारी के संरक्षण के वास्ते कौशलों के उन्नयन और पैतृक कौशलों में ''कलाओं, संसाधनों और वस्तुओं में परंपरागत कौशलों का उन्नयन'' नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा, जो कि एक समृद्ध विरासत है.

मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये बजट में रू 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई है.

11. नीरांचल

देश में जलग्रहण विकास को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिये, वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू 2142 करोड़ के शुरूआती परिव्यय के साथ ''नीरांचल'' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया जायेगा. पशमीना प्रोत्साहन कार्यक्रम (पी–3) और जम्मू एवं कश्मीर के अन्य शिल्पों के विकास के लिये भी कार्यक्रम शुरू किये जाने हैं. इसके लिये रू 50 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है.

12. वित्तीय समावेशन मिशन

देश में सभी घरों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये 2014 में 15 अगस्त को वित्तीय समावेशन मिशन के तौर पर एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जायेगा. इसमें महिलाओं, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा श्रमिकों सहित समाज के कमज़ोर वर्गों पर विशेष फ़ोकस रहेगा. प्रत्येक घर में दो बैंक खाते खोलने का प्रस्ताव है, जो ऋण के लिये पात्र होंगे.

13. 2022 तक सभी के लिये घर

सरकार ने शहरी गरीबों/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों/अल्प आय वर्गों को किफ़ायती आवास के लिये सस्ते ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास बैंक में संचालित किये जाने वाले कम लागत किफायती आवास पर एक मिशन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है. सरकार पहले ही इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सुगम प्रवाह जैसे कुछ अन्य प्रोत्साहनों का उल्लेख कर चुकी है और अन्य सकारात्मक सुझावों पर विचार करने की इच्छुक है. सरकार ने इस गतिविधि के प्रति अधिक योगदान के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की सूची में झुग्गी–झोपड़ी (स्लम) विकास को शामिल कर लिया है.

New Social Welfare Schemes in the Annual Budget 2014-15.

Finance Minister Arun Jaitley submitted his maiden budget for the financial year 2014-15. Some new social development schemes to address the critical issues of the country have been introduced.

1. **Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana**
   The FM announced this programme in the Budget as a measure to mitigate the risk of monsoon dependent irrigation. The scheme is aimed to give assured irrigation to farmers. The FM proposed to set aside a sum of 1000 crore for this purpose.

2. **Swatchh Bharat Abhiyan**
   Total sanitation by 2019, is the slogan of this programme. Realizing the importance of the sanitation the FM has sought the help of every citizen to achieve this goal. The year 2019 also marks the 150th Birth anniversary of Mahatma Gandhi.

3. **Soil Health Card Scheme for Every farmer**
   The government has initiated this scheme concerning the deteriorating the soil health which leads to sub-optimal utilization of farming resources. The government will initiate to provide every farmer a soil health card a in a mission mode. A sum of Rs. 100 crore is allotted. An additional Rs. 56 crores have been allocated to set up 100 mobile soil testing laboratories across the country.

4. **A Dedicated TV Channel for Farmers**
   Kisan TV, dedicated to the interests of the agriculture and allied sector will be launched in the current financial year. This will disseminate real time information to the farmers regarding new farming techniques, water conservation, organic and farming etc.,

5. **Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana**
   ñDeendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojanaò for feeder separation will be launched to augment power supply to the rural areas and for strengthening sub-transmission and distribution systems. Its long-term aim is to provide 24×7 uninterrupted power supply to all homes. A sum of Rs. 500 crores has been set aside for this scheme.

6. **Van Bandhu Kalyan Yojana**
   For the welfare of the tribal people ñVan Bandhu Kalyan Yojanaò is being launched with an initial allocation of Rs. 100 crore.

7. **Beti Bachao, Beti Padhao Yojana**
   Government has introduced a new scheme called Beti Bachao, Beti Padhao, which will help in generating awareness and improving the efficiency of delivery of welfare services meant for women with an initial corpus of Rs 100 crore. The government would focus on campaigns to sensitize people of this country towards the concerns of the girl child and women. The process of sensitization must begin early and therefore the school curriculum must have a separate chapter on gender mainstreaming.

8. **National Heritage City Development and Augmentation Yojana**
   The programme called Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) is to be launched for conserving and preserving the heritage characters of these cities. For the beginning programme is launched in the cities such as Mathura, Amritsar, Gaya, Kanchipuram, Vellankani and Ajmer. A sum of Rs. 200 crores is set aside for this purpose. The Project will work through a partnership of Government, academic institutions and local community combining affordable technologies.

9. Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission

Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission will be launched to deliver integrated project based infrastructure in the rural areas. The scheme will also include development of economic activities and skill development. The preferred mode of delivery would be through PPPs while using various scheme funds. It is based on the example of Gujarat that has demonstrated successfully the Rurban development model of urbanization of the rural areas, through which people living in the rural areas can get efficient civic infrastructure and associate services.

10. Minorities

A programme for the upgradation of skills and training in ancestral arts for development for the minorities called ñUpgradation of Traditional Skills in Arts, Resources and Goodsò is to be launched to preserve the traditional arts and crafts, which are rich heritage.

An additional amount of ` 100 crores for Modernization of Madarsas has been in the Budget provided to the Department of School Education.

11. **Neeranchal**

To give an added impetus to watershed development in the country, a new programme called ñNeeranchalò with an initial outlay of ` 2,142 crores in the current financial year. Pashmina Promotion Programme (P-3) and a programme for the development of other crafts of Jammu & Kashmir is also to be started. For this a sum of Rs. 50 crores is set aside.

12. Financial Inclusion Mission

To provide all households in the country with banking services, a time bound programme is to be launched as Financial Inclusion Mission on 15 August in 2014. It would particularly focus to empower the weaker sections of the society, including women, small and marginal farmers and labourers. Two bank accounts in each household are proposed to be opened which will be eligible for credit.

13. Housing for All by 2022

Government has proposed to set up a Mission on Low Cost Affordable Housing to be anchored in the National Housing Bank with a view to increase the flow of cheaper credit for affordable housing to the urban poor/EWS/LIG segment. The government has already outlined some other incentives such as easier flow of FDI in this sector and is willing to examine other positive suggestions. The government has included slum development in the list of Corporate Social Responsibility (CSR) activities to encourage the private sector to contribute more towards this activity.